चावल की जगह गेहूं की मात्रा बढ़ाए केंद्र

मंत्री राजपूत केंद्रीय मंत्री जोशी से मिले, व्यापारी हितग्राहियों से कम दाम में खरीदते हैं चावल

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 19 जुलाई. सार्व जनिक वितरण प्रणाली के तहत पात्र हितग्राहियों को दिये जा रहे खाद्यान्न में चावल की जगह गेहूं की मात्रा बढ़ाई दी जाये. मध्यप्रदेश में चावल की जगह गेहूं का उपयोग बहुतायत में होता है.

समय - समय पर यह देखने में आता है कि कुछ व्यापारी हितग्राहियों को प्रलोभन देकर उनसे कम दाम में चावल खरीद लेते है, जिससे बाजार में दुरूपयोग की घटनाएं सामने आती हैं. इस समस्या के समाधान के लिये मप्र में पात्र हितग्राहियों को दिये जाने वाले खाद्यान्न में गेहूं की मात्रा बढ़ाई जाना हितकारी होगा. खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत ने यह सुझाव नई दिल्ली में केन्द्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी से भेंट के दौरान दिया. इस दौरान केन्द्रीय खाद्य मंत्री को मप्र में उपार्जन केंद्रों में सुविधाओं के विस्तार और गुणवत्ता सुधार के संबंध में किये जा रहे प्रयासों से अवगत कराया. साथ ही बताया कि प्रदेश में विकेन्द्रीयकृत उपार्जन योजना के तहत समर्थन मूल्य पर उपार्जित गेहूं में से सरप्लस मात्रा उपार्जन अवधि के बाद गोदामों से सी-मोड में भारतीय खाद्य निगम को प्रदान की जाती है. वर्ष 2021-22 के लिये 2.89 प्रति क्विंटल लोडिंग एव हेण्डलिंग व्यय की स्वीकृति नहीं की गई थी. मंत्री राजपूत ने अनुरोध किया कि भारतीय खाद्य निगम द्वारा गोदामों से उठाव किये गये गेहूं की लोडिंग एवं हेण्डलिंग व्यय की राशि अभी तक स्वीकृत नहीं की गई, जिसे शीघ्र जारी किया जाए.

1500 करोड़ का अनुदान भुगतान जल्द कराने का आग्रह

खाद्य मंत्री राजपूत ने केंद्रीय खाद्य मंत्री जोशी को अवगत कराया कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत वर्ष 2020-21 से 2022-23 तक की अवधि में पात्र परिवारों को वितरित किये गये खाद्यान्न- का डाटा भारत सरकार के अन्न वितरण पोर्टल पर उपलब्ध है. इस डाटा को भारत सरकार के सेंट्रल रिपोजिटरी पोर्टल पर अपलोड करने की अनुमति देने के साथ 1500 करोड़ के अनुदान राशि के बकाया भुगतान को जल्द किये जाने का अनुरोध किया. इस पर केन्द्रीय मंत्री जोशी ने अधिकारियों से चर्चा कर जल्द भुगतान कराये जाने का भरोसा दिया. राजपूत ने केन्द्रीय खाद्य मंत्री से खरीफ विपणन वर्ष 2014-15 से 2018-19 तक के समर्थन मूल्य पर उपार्जित 2.95 लाख मीट्रिक टन मोटे अनाज के उपार्जन प्लान की स्वीकृति दिये जाने का अनुरोध किया है. भारत सरकार की नीति के अनुसार समर्थन मूल्य पर उपार्जित मोटे अनाज का वितरण राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत पात्र परिवारों को गेहूं के आवंटन के विरूद्ध वितरण कराया जा चुका है. मंत्री राजपूत ने केन्द्रीय मंत्री को अवगत कराया कि उपार्जन प्लान की स्वीकृति प्राप्त न होने से वितरित किये गये मोटे अनाज पर मिलने वाली अनुदान की राशि लंबित है, जिसका शीघ्र भुगतान कराया जाये.

कमीशन की राशि बढ़ाए जाने का अनुरोध

केन्द्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री जोशी से मुलाकात के दौरान खाद्य मंत्री राजपूत ने बताया कि समर्थन मूल्य पर खाद्यान्न उपार्जन करने वाली सहकारी संस्थाओं को गेहूं एवं धान के उपार्जन पर मिलने वाले कमीशन में 2013 के बाद से कोई वृद्धि नहीं की गई है, जबकि अन्य राज्यों को कमीशन मद में अधिक राशि का भुगतान किया जा रहा है. समितियों को उपार्जन कार्य में हो रहे व्यय की प्रतिपूर्ति न होने से हो रही हानि से अवगत कराते हुये खाद्य मंत्री राजपूत ने केन्द्र सरकार से उपार्जन पर कमीशन की राशि 43 रूपये प्रति क्विंटल किये जाने का अनुरोध किया.

तेज रफ्तार बस ने बाइक को मारी टक्कर, 2 युवकों की मौत

धार, 19 जुलाई. प्रदेश में रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है. ताजा मामला धार जिले के निसरपुर चौकी क्षेत्र का है, जहां तेज रफ्तार बस और बाइक की आमने-सामने की भिड़ंत में दो युवकों की दर्दनाक मौत हो गई.

हादसे के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई,घटना खंडवा-बड़ौदा राजमार्ग-26 पर हुई. बड़वानी से मनावर जा रही एक यात्री बस जब सड़क किनारे स्थित पेट्रोल पंप पर डीजल भरवाने के लिए मुड़ी, तभी सामने से आ रही बाइक से जोरदार टक्कर हो गई.

टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. घायल को तत्काल बड़वानी अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई. दोनों युवक डेहरी चौकी अंतर्गत लुन्हेरा लोगसरी गांव के निवासी बताए जा रहे हैं.

मंत्रालय के गलियारों से

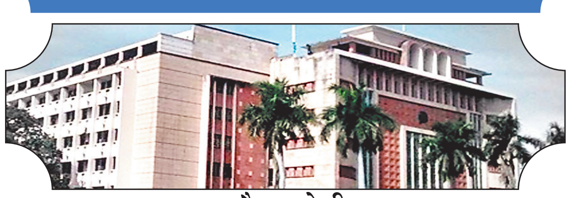

कन्हैया लोधी

अब पद का पावर दिखने लगा

पिछले विधानसभा चुनाव में केंद्र की राजनीति करने वाले कुछ नेताओं को मप्र की राह दिखा दी गई थी. ये नेता दिल्ली से वापस प्रदेश की राजनीति में आये तो कुछ समय तो समझ ही नहीं आया, वे लोकसभा चुनाव में बदलाव की उम्मीद बांधे थे, लेकिन वह वक्त भी निकल गया, तब समझ आया कि प्रदेश में जो मिला है, उसी से काम चलाना पड़ेगा. ये बात एक बड़े नेता जो कि बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, उनको जरा देर से समझ आई. नेताजी लंबे समय तक अनमने से रहे, जो जिम्मेदारी मिली, उसे निभाते तो रहे, लेकिन बुझे मन से, लेकिन अब वे पद का पॉवर दिखाने लगे हैं. पिछले दिनों राजधानी में उन्होंने अपना पॉवर दिखाया, आधा दर्जन से अधिक राज्यों के बड़े पदाधिकारियों की उन्होंने एक कार्यक्रम के बहाने मेजबानी की और बता दिया कि उनका एक बुलावा काफी है.

क्या तीर निशाने पर लगेगा

देश में इस समय भाजपा का भावी राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम कौतुहल का विषय है कि आखिर वह होगा कौन. इस पद के लिए वैसे तो कई कद्दावर मैदान में है, इनमें मप्र के भी एक बड़े नेता शामिल है. इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री दीदी ने सार्वजनिक ऐलान कर दिया कि उन्हें उनकी ही सरकार के समय प्रताड़ित किया गया, अब सवाल ये उठता है कि दीदी को आखिर अपनी पीड़ा इसी वक्त ही नजर क्यों आई. पहले भी आ सकती थी और फिर अध्यक्ष का चयन हो जाने के बाद भी आ सकती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं. अब राजनीतिक विश्लेषक उनके बयान के मायने निकालने में लगे हैं. सवाल ये है कि उनका तीर क्या निशाने पर लगेगा. ये तस्वीर कुछ समय बाद साफ हो जायेगी.

लूपलाइन के पद को मेन स्ट्रीम का बनाया

एक अपर मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी को पिछले दिनों एक बड़ी जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया गया, उसके बाद भी साहब के पास एक बड़े विभाग की जिम्मेदारी बनी हुई है, साथ ही उनके पास एक अतिरिक्त जिम्मेदारी भी है. ये अतिरिक्त जिम्मेदारी वाला पद मंत्रालय में कभी सुपर लूप लाइन माना जाता था, लेकिन साहब ने इस पद को लेकर ऐसी सक्रियता दिखाई कि ये लूप लाइन का पद अब मेन स्ट्रीम के पद में शुमार हो गया है. दरअसल विभाग की ज्यादातर फाइलें साहब के पास दौड़ने लगी है. वैसे ये स्थिति कब तक बनी रहेगी, कह नहीं सकते, क्योंकि विभाग अभी बिना पीएस के ही चल रहा है.

पीएस जो मंत्रालय के अलावा कहीं भी मिलेंगे

यदि कोई प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी हैं, तो सामान्य रूप से उम्मीद की जाती है कि वे मंत्रालय में नियमित रूप से बैठेंगे, लेकिन एक पीएस पर ये बात लागू नहीं होती. साहब मंत्रालय के अलावा कहीं भी मिलेंगे. स्टॉफ के मुताबिक मंत्रालय में साहब के दर्शन दुर्लभ हैं. मंत्रालय से जुड़ी जरुरी फाइलें भी वे बाहर अतिरिक्त जिम्मेदारी वाले कार्यालयों में ही बुलवा लेते हैं. वैसे साहब को महकमे में लंबा समय हो गया है. बताया जा रहा है कि सरकार की कृपा उन पर बनी हुई है, लेकिन ये कृपा कब तक बनी रहेगी, ये देखना दिलचस्प होगा.

40 जिलों में फिर झमाझम बरसेंगे बदरा

▸ गरज-चमक के साथ चलेंगी तेज हवाएं

नवभारत रिपोर्टर

भोपाल, 19 जुलाई. मप्र के कई हिस्सों में अगले 24 घंटों के दौरान गरज -चमक के साथ बारिश हो सकती है. रविवार को करीब 40 जिलों में बारिश होने के आसार हैं.

जिसमें भोपाल, विदिशा, रायसेन, सिहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगौन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगर, मंदसौर, नीमच, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुरकलां, सागर जिलों में बारिश के आसार बने हुए हैं. इसके साथ ही सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, अनुपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, पन्ना, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, मैहर, पांढुर्णा जिलों में भी बारिश की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है. प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र के जिलों में बाढ़ा की संभावना भी मौसम विभाग ने जताई है. इन क्षेत्रों के रहवासियों को प्रशासन द्वारा अलर्ट पूर्व से ही किया गया है. प्रदेश में फिलहाल मूसलाधार बारिश होने की संभावना जताई गई है. इस दौरान 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी.

6 फर्जी क्लिनिकों पर कार्रवाई

ग्वालियर, 19 जुलाई. स्वास्थ्य विभाग ने ग्वालियर में फर्जी चिकित्सा पद्धतियों पर शिकंजा कसते हुए दो दिनों में 6 क्लिनिकों को सील किया है.

सीएमएचओ की टीम ने ऐसे क्लिनिक पकड़े, जो बिना पंजीकरण के और अयोग्य व्यक्तियों द्वारा चलाए जा रहे थे. जांच में पाया गया कि ये क्लिनिक सीएमएचओ कार्यालय में पंजीकृत नहीं थे और इनमें इलाज करने वाले अधिकतर लोग उचित चिकित्सकीय योग्यता नहीं रखते थे. विभाग का कहना है कि ऐसे फर्जी क्लिनिक मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं.

बिना योग्यता कर रहे थे एलोपैथिक इलाज

डॉ. हनीफ खान ग्राम शंकरपुर में अवैध रूप से एलोपैथिक इलाज करते पाए गए. डॉ. राहुल सेंगर बहोड़ापुर, किशन बाग में क्लिनिक संचालित कर एलोपैथिक इलाज कर रहे थे. संतोष सिंह राणा बीए पास होने के बावजूद शंकरपुर में दंत चिकित्सा करते पाए गए. डॉ. कान्ति पंथ योग्यता से बाहर एलोपैथिक इलाज करते पकड़े गए. टीके विश्वास सिकंदर कम्पू क्षेत्र में बिना रजिस्ट्रेशन एलोपैथिक इलाज करते मिले. बृज किशोर प्रजापति सिकंदर कम्पू में एलोपैथिक और होम्योपैथिक दोनों तरह के इलाज में संलिप्त थे.

गड्ढों में समाई दो मासूमों की सांसें, मौत

खंडवा, 19 जुलाई. खंडवा जिले में सरकारी लापरवाही ने दो मासूमों की जान ले ली. सुरगांव निपनी गांव में गड्ढे में भरे पानी में डूबने से 2 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई.

यह हादसा हाईवे निर्माण कार्य में छोड़े गए गड्ढों के कारण हुआ, जिनमें बारिश का पानी भर गया. गांव के दो बच्चे भैंस चराने निकले थे और खेलते-खेलते गड्ढे में नहाने लगे. तभी गहराई में फंस जाने से डूब गए. परिजनों का आरोप है कि हाईवे निर्माण कंपनी ने सड़क निर्माण के लिए कई जगह गहरे गड्ढे खोद रखे हैं, लेकिन उन्हें सुरक्षित करने का इंतजाम नहीं किया. स्थानीय लोग निर्माण एजेंसी पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. जिस विकास के नाम पर गड्ढे खोदे जा रहे हैं, वही अब लोगों की जिंदगियां निगलने लगे हैं. लापरवाही की कीमत मासूमों की जान से चुका रहे हैं.

संगठन | जिला अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर कांग्रेस में संगठनात्मक हलचल

अध्यक्ष पटवारी और उमंग दिल्ली तलब

भोपाल, 19 जुलाई. मध्यप्रदेश कांग्रेस संगठन में बड़ी फेरबदल की तैयारी है. जिला कांग्रेस अध्यक्षों की नियुक्ति से पहले प्रदेश के शीर्ष नेताओं को दिल्ली बुलाया गया है.

पार्टी आलाकमान ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार को अलग-अलग समय पर दिल्ली बुलाया है. सूत्रों के अनुसार, 22 जुलाई को जीतू पटवारी दिल्ली जाएंगे, जबकि 23 जुलाई को उमंग सिंघार की दिल्ली यात्रा तय की गई है. बताया जा रहा है कि यह बुलावा एआईसीसी ऑब्जर्वर की रिपोर्ट के आधार पर हुआ है, जिसमें जिला अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर नेताओं से अलग-अलग राय ली जानी है.

इन बैठकों के बाद जिला अध्यक्षों के नामों पर मंथन शुरू होगा और अगस्त के पहले सप्ताह में नई सूची जारी की जा सकती है. कांग्रेस के 'संगठन सृजन कार्यक्रम' के तहत यह प्रकिया चलाई जा रही है, जिसकी शुरुआत राहुल गांधी ने भोपाल से की थी. इस राजनीतिक गतिविधि को प्रदेश कांग्रेस के संगठनात्मक पुनर्गठन की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है.

एनएसयूआई में बड़ा बदलाव

भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन ने संगठनात्मक मजबूती के उद्देश्य से बड़ा फेरबदल किया है. एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी ने दिल्ली के अंकित डेढ़ा और हरियाणा के साहिल शर्मा को मध्यप्रदेश एनएसयूआई का नया स्टेट प्रभारी नियुक्त किया है. यह नियुक्ति आगामी छात्रसंघ चुनावों और संगठन को जमीनी स्तर पर सशक्त करने के दृष्टिकोण से की गई है. इस बदलाव के तहत राजस्थान के महावीर गुर्जर और रितू बराला को उनके प्रभारी पद से हटा दिया गया है. सूत्रों का कहना है कि यह फैसला संगठन में नई ऊर्जा और रणनीति लाने की दिशा में अहम माना जा रहा है. नए प्रभारियों अंकित डेढ़ा और साहिल शर्मा को उनकी सक्रियता और नेतृत्व कौशल के आधार पर यह जिम्मेदारी सौंपी गई है.

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्रा. लि. हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा.लि. के लिए आशीष श्रोती द्वारा 3, इंदिरा प्रेस कॉम्प्लेक्स, रामगोपाल माहेश्वरी मार्ग, महाराणा प्रताप नगर, जोन-1, भोपाल से प्रकाशित एवं नवभारत प्रेस भोपाल प्रा.लि., इंदिरा प्रेस कॉम्प्लेक्स से मुद्रित. संपादक दिलीप झा*, *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत जिम्मेदार, फोन-4939198, ईमेल-bhopalnav@gmail.com RNI Reg. No. 35046/56 डाक पंजीयन क्रमांक M.P/B.P.L/711/2012-14